PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 016
दि. 16.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत सहयोग देने को तैयार', पीएम मोदी के ऐलान के बाद यूएई का सीना चौड़ा

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के साये के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा ने दुनिया को भारत की 'शांतिदूत' वाली छवि का अहसास कराया है. अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है.

,,

अबू धाबी : मिडिल ईस्ट में जंग के हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई लैंड हुए हैं. अबू धाबी की धरती से पूरी दुनिया को भारत की ताकतवर विदेश नीति का एहसास करा दिया है. यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ हुई हाई-लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति की बहाली के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है. हाल के दिनों में यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए मोदी ने ये भरोसा दिलाया कि भारत हर परिस्थिति में अपने इस 'भाई' जैसे दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है.

पीएम मोदी ने कहा 'UAE के साथ खड़ा भारत'

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है. मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि खाड़ी देश ने जिस तरह से संयम रखते हुए मौजूदा स्थिति को संभाला है वो तारीफ के काबिल है. अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ अपनी मुलाकात के दौरान, मोदी ने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा.

पश्चिम एशिया में अस्थिर स्थिति का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा, 'भारत शांति और स्थिरता की बहाली के लिए जल्द से जल्द हर

संभव सहयोग देने को तैयार है'.

प्रधानमंत्री मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित पारगमन मार्ग और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने के पक्ष में भारत की स्पष्ट स्थिति को भी व्यक्त किया, जो कि स्थायी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के साथ-साथ ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, 'होर्मुज जलडमरूमध्य को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है'. साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना आवश्यक है.

बीती 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था. मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच विस्तृत चर्चा हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और खाड़ी देश के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता को दोहराया.

भारत-यूएई की दोस्ती

पीएम मोदी ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा, 'हम यूएई में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं. यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, वो किसी भी रूप में अस्वीकार्य है'. प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति से कहा, 'इन कठिन परिस्थितियों में आपके द्वारा प्रदर्शित संयम और साहस बहुत प्रशंसनीय है'. मोदी ने ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय समुदाय की अपने परिवार के सदस्यों की तरह ध्यान रखने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया.

88 विदेशी जहाज ब्लैक लिस्ट- 278 पर बैन, भारतीयों संग बुरे बर्ताव पर गुस्साई सरकार, चलाया हंटर

(जीएनएस)।

13 मई को ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाज हाजी पर हमला किया गया जिसमें जहाज डूब गया। इस पर भारत सरकार ने गुस्सा जताया था और कहा था कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अब सरकार ने इस घटना के ठीक बाद एक बड़ा कदम उठाया है जिसका असर 366 विदेशी जहाजों पर पड़ेगा।

दरअसल भारतीय समुद्री नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए 366 विदेशी झंडो वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को काम पर रखने पर रोक लगा दी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री युद्ध के बीच हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसारइन जहाजों पर चालक दल को छोड़ देने, समय पर वेतन नहीं देने, मौत या लापता होने की स्थिति में मुआवजा न देने, कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न-अमानवीय व्यवहार करने और भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस घर नहीं भेजने जैसे गंभीर आरोप लगे

थे।

DG Shipping ने कहा कि कई विदेशी जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों और भारत के समुद्री सुरक्षा कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। इसी वजह से सरकार ने RPSLरखने वाली कंपनियों को चेतावनी दी कि वे इन जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात न करें। सरकार का मानना है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। खासकर ऐसे समय में जब वेस्ट एशिया का समुद्री क्षेत्र युद्ध की चपेट में हो। जारी सर्कुलर में बताया कि कुल 366 जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से 278 जहाजों को Restricted यानी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है, जबकि 88 जहाजों को सीधे Blacklisted कर दिया गया, मतलब ही इनसे शायद ही कभी भविष्य में काम लिया जाए। इसके साथ ही सभी प्फ्ढरछ कंपनियों को आदेश दिया गया कि वे 14 दिनों के भीतर उन भारतीय नाविकों की पूरी जानकारी जमा करें जो इन जहाजों पर काम कर रहे हैं।

अपने आधिकारिक आदेश में उफ्फ़ ग्रॅंस्रप्र्ल्लॅ ने साफ कहाः 'नाविकों के बेहतर भविष्य, उन्हें छोड़ देने की घटनाओं और इंटरनेशनल सी एग्रीमेंट्स के उल्लंघन को देखते हुए, 366 जहाजों पर भारतीय नाविकों की भर्ती तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की जाती है, जब तक कि उचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो जाता।'

प्रधानमंत्री मोदी की अपील की गुजरात में बड़ा असर, दो दिनों में पायलट वाहनों की मांग घटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सरकारी यात्राएं कम करने की अपील का गुजरात में बड़ा असर देखने को मिला है। पिछले दो दिनों में पायलट वाहनों की मांग में कमी दर्ज की गई है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने पिछले दो दिनों में गृह विभाग को पायलट वाहन के लिए आने वाली कॉल्स में कमी की जानकारी दी।

गांधीनगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सरकारी यात्राएं कम करने की अपील का गुजरात में बड़ा असर देखने को मिला है। पिछले दो दिनों में पायलट वाहनों की मांग में कमी दर्ज की गई है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने पिछले दो दिनों में गृह विभाग को पायलट वाहन के लिए आने वाली कॉल्स में कमी की जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक से पहले कहा कि पायलट वाहनों की संख्या घटाने से ईंधन के इस्तेमाल और मैनपावर में काफी बचत हुई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने के प्रयास भी तेज किए हैं।

नए उपायों के असर पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए संघवी ने कहा, "कुल मिलाकर दो दिनों में 126 कॉल्स की कमी आई है।"

उन्होंने कहा कि अगर कम से कम अनुमान भी लगाया जाए, तो इस कमी से लगभग 5,000 किलोमीटर तक पेट्रोल और डीजल की खपत में बचत हो सकती है। उन्होंने कहा, "अगर हम हर कॉल के लिए औसतन 25 से 50 किलोमीटर की दूरी मान लें, तो कम से कम 5,000 किलोमीटर के बराबर डीजल और पेट्रोल की बचत होगी।"

उन्होंने आगे बताया कि इस बचत पर एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हर्ष संघवी ने यह भी बताया कि हर पायलट वाहन की तैनाती में कुछ कर्मचारी शामिल होते हैं, जिन्हें अब दूसरे कामों में लगाया जा सकता है।

राज्य सरकार ने ये कदम प्रधानमंत्री मोदी की हालिया सार्वजनिक अपील के बाद उठाए हैं, जिसमें उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने, कारपूलिंग अपनाने और जहां संभव हो, अधिकतर बैठकें ऑनलाइन करने का आग्रह किया था।

इस अपील के बाद से गुजरात के प्रशासनिक कामकाज में कई बदलाव किए गए हैं। मंत्रियों ने अपने काफिले को छोटा किया है, जबकि विभागों को सलाह दी गई है कि जहां भी व्यावहारिक हो, वे वर्चुअल बैठकें करें।

संघवी ने कहा कि गांधीनगर तक की अनावश्यक यात्रा कम करने पर खास फोकस है। उन्होंने कहा, "दूर के शहरों से आने वाले लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से रोका गया है।"

पीएम मोदी इस साल करेंगे रूस दौरा : लावरोव

नई दिल्ली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल के अंत में रूस जाएंगे। लावरोव के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान खुद इस बात की पुष्टि की।

गुरुवार को लावरोव ने नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। लावरोव ने भारत में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि मास्को कई क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लावरोव ने कहा, "हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि इस वर्ष रूस का दौरा करने की उनकी बारी है।

गृह मंत्री को धमकी देने के आरोप में ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी भतीजे पर एफआईआर, कौन-कौन सी लगी धाराएं?

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित होने के महज एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर को राज्य पुलिस द्वारा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की लिखित शिकायत पर बागुइयाटी पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक शिकायत दर्ज हुई, जिसे बाद में साइबर क्राइम यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने अभिषेक बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर दिए गए भड़काऊ भाषणों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप लगाया है।

एफआईआर में कौन-कौन सी धाराएं?

पुलिस ने कुल 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हैः

BNS 192 (जमानती)ः दंगे भड़काने से संबंधित।

BNS 196 (गैर-जमानती)ः विभिन्न समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ना और घृणा फैलाना।

BNS 351(2) (गैर-जमानती)ः मृत्यु की धमकी देना और मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाना।

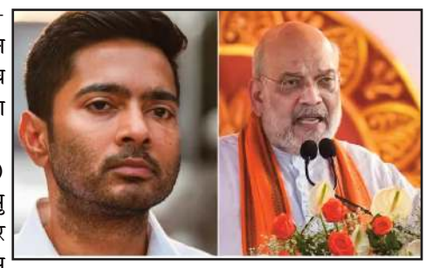

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125ः चुनाव प्रचार के दौरान भ्रामक बयान, दबाव और समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना।

ये धाराएं गंभीर हैं और अभिषेक बनर्जी की संसदीय सदस्यता तथा राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकती हैं।

विवाद की जड़ः चुनावी रैलियों में दिए गए भाषण

2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। परिणाम आने से पहले और बाद में अभिषेक बनर्जी ने कई रैलियों में इखढ, अमित शाह, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए थे। शिकायतकर्ता राजीव सरकार ने अभिषेक के विभिन्न भाषणों के वीडियो लिंक और क्लिप्स संलग्न कर शिकायत दी। आरोप है कि इन भाषणों मेंः अमित शाह को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर धमकी भरे बयान दिए गए।

विभिन्न समुदायों और राजनीतिक विरोधियों के बीच वैमनस्य फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भ्रामक बयान दिए गए।

अभिषेक बनर्जी ने पहले भी अमित शाह पर तीखे हमले किए थे और 'बंगाल में BJP को घुसने नहीं देंगे' जैसे आक्रामक बयान दिए थे।

2026 के चुनाव में TMC की हार के बाद पार्टी के अंदर और बाहर कई सवाल उठ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को पार्टी का दूसरा सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। ममता बनर्जी के भतीजे होने के नाते उनकी भूमिका हमेशा चर्चा में रही है।

हार के बादः TMC नेताओं के एक वर्ग ने अभिषेक की रणनीति और क्ढअउ (I-PAC) जैसी एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए। विपक्ष (BJP) ने TMC पर हिंसा, धमकी और ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अभिषेक ने खुद चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाए और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही।

इसी माहौल में यह एफआईआर दर्ज हुई है, जिसे राजनीतिक प्रतिशोध भी माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले में भोजशाला में अब मुसलमानों को नमाज पर रोक, मुस्लिम पक्ष बोला- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला विवादित परिसर को मां वाग्देवी (सरस्वती) का प्राचीन मंदिर घोषित कर दिया। शुक्रवार (15 मई) को दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार दे दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष को परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं रहेगी। कोर्ट ने 2003 के अरक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दोनों समुदायों को तय समय पर इबादत की अनुमति थी।

यह फैसला न केवल भोजशाला विवाद का महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा जैसे अन्य मामलों की श्रृंखला में पुरातात्विक साक्ष्यों, एएसआई सर्वे और Places of Worship Act 1991 की व्याख्या पर नई बहस छेड़ता है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को स्वीकार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की है।

वकील विष्णु शंकर जैन (हिंदू पक्ष) ने कहा, 'यह ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने भोजशाला को राजा भोज का मंदिर माना। अरक का 2003 का ऑर्डर रद्द हो गया। अब यहां सिर्फ हिंदू पूजा होगी। कोर्ट ने सरकार को साइट मैनेजमेंट और मूर्ति वापसी पर विचार करने को कहा है।' धार शहर काजी वकार सादिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हम फैसले का रिव्यू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।'

भोजशाला का ऐतिहासिक बैकग्राउंड कैसा है? परमार वंश का स्वर्ण युगः 11वीं शताब्दी में राजा भोज (1010-1055 ई.) ने धार को राजधानी बनाया। वे विद्वान शासक थे जिन्होंने समरांगण सूत्रधार जैसे ग्रंथ लिखे। भोजशाला को सरस्वती सदन या वाग्देवी मंदिर के रूप में स्थापित किया गया, जो प्राचीन भारत का प्रमुख विद्या और संस्कृत अध्ययन केंद्र था।

13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों (अलाउद्दीन खिलजी, दिलावर खान आदि) के दौरान कई हिंदू संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुईं। 15वीं शताब्दी में मालवा सल्तनत के दौरान सूफी संत कमाल मौला की दरगाह बनी। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है।

1875ः खुदाई में वाग्देवी प्रतिमा मिली, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में है। हिंदू पक्ष इसे वापस लाने की मांग करता रहा।

कानूनी संघर्षः 1995 से 2026 तक

1995ः छोटे विवाद के बाद प्रशासन ने मंगलवार को हिंदू पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी।

1997ः दिग्विजय सिंह सरकार के समय प्रतिबंध और फिर शर्तों के साथ अनुमति।

फ्यूल की कीमतों में महा-उछाल से छिड़ा सियासी संग्राम, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने कहा-'महंगाई मैन मोदी ने एक बार फिर जनता पर कोड़ा चला दिया

(जीएनएस)।

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुक्रवार, 15 मई को ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। लंबे समय से आशंका जताई जा रही थी कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट का असर भारत में ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है।

आखिरकार सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ा दिए। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील कर चुके हैं।

नई कीमतें लागू होने के बाद देशभर में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया है, जबकि BJP नेताओं का कहना है कि वैश्विक हालात को देखते हुए सरकार ने बढ़ोतरी को न्यूनतम रखने की कोशिश की है।

कांग्रेस ने ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार ने जनता पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया है।

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा-"महंगाई मैन मोदी ने एक बार फिर जनता पर कोड़ा चला दिया है। पेट्रोल-डीजल 3-3 रुपये महंगा कर दिया गया। CNG के दाम भी बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू।"

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं तब भी सरकार ने टैक्स कम नहीं किए और अब वैश्विक संकट का हवाला देकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के BJP नेता दिलीप घोष ने कहा कि दुनिया पिछले कई वर्षों से युद्ध और आर्थिक संकट झेल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बड़े नुकसान से बचाए रखा।

उन्होंने कहा,-दुनिया में तीन साल से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। कई देशों में भारी संकट है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों को बचाने की कोशिश की है। कीमतें जितनी बढ़ सकती थीं, उससे काफी कम बढ़ाई गई हैं।"

सम्पादकीय

तमाम प्रेशर प्रयास के बावजूद नहीं खुल रहा होर्मूज जलडमरू

पश्चिम एशिया में इस वक्त तनाव का मुख्य केन्द्र बना हुआ है जहां बुधवार को सुबह भारत के ध्वज वाली मशीनी पाल नौका हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में हमले का शिकार हो गई।

पोत पर सवार सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक दल ने सुरक्षित बचा लिया है। भारत सरकार ओमान प्रशासन और भारतीय राजदूतावास के साथ मिलकर सभी को भारत लाने का प्रयास कर रही है। दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने जब हमला करके उनके नेताओं, शीर्ष सैन्य अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों का सफाया कर दिया तो तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तो हमला किया ही साथ ही उन देशों की सम्पत्तियों को भी निशाना बनाया जो अमेरिका द्वारा संरक्षित घोषित की गई हैं। युद्ध के दौरान पूरी दुनिया को अपने रणनीतिक महत्व का एहसास दिलाने के लिए होर्मूज जलडमरूमध्य को बाधित कर दिया। चुछ मित्र देशों को छोड़कर ईरान ने सभी देशों की जहाजों को इस क्षेत्र से गुजरने की छूट नहीं दी।

अमेरिका ने जलडमरूमध्य से निर्बाध जहाजों को गुजरने के लिए ईरान को धमकाया भी किन्तु वहां की सेना और सिविल प्रशासन ने एक न सुनी। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने भी जलडमरूमध्य की घेराबंदी कर दी। आज भी ईरान और अमेरिका दोनों के सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं।

सच तो यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध विराम हुआ है वह कभी भी दोबारा टूट सकता है। इस बार यदि युद्ध भड़का तो वह इतना विकराल होगा कि ईरान तो बर्बाद होगा ही खाड़ी के देश भी तबाह हो जाएंगे।

सच तो यही है कि एलपीजी गैस की महंगाई के वजह से 42 महीनों में भारत की मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत पार कर गई है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था रूपी शरीर का मधुमेह होता है। इससे देश, संस्थानों और निजी आर्थिक स्थिति पर प्रतिवूल प्रभाव पड़ता है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की संभावित कीमतों का अनुमान लगाकर ही देशवासियों से ईंधन कम खर्च करने का आग्रह करके इस बात की चेतावनी दी है कि यदि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध दोबारा छिड़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिवूल असर पड़े बिना नहीं रहेगा। इसलिए देश की जनता पहले से ही पेट्रोल, डीजल और वुकिग गैस को ज्यादा खर्च न करें अन्यथा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी कम से कम खर्च करने के अनुरोध के तुरन्त बाद खुद ही अपने काफिले में शामिल होने वाली 14 गाड़ियों को कम करके मात्र तीन गाड़ी में सीमित कर दिया। मतलब यह कि एक गाड़ी में खुद प्रधानमंत्री, एक गाड़ी अतिरिक्त और एक में सुरक्षाकमी होंगे। इसी तरह केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों में 80 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। प्रधानमंत्री के आ'ान पर राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों ने काफिले को छोटा करके प्रधानमंत्री मोदी के पैसले का समर्थन किया है। बहरहाल एक जहाज के हमले की चपेट में आने अथवा घात लगाकर हमला किए जाने से जलकर वह डूब गया। यह भारत के लिए अत्यन्त दुःख और चिन्ता बढ़ाने वाली बात है। इसलिए अब देश के सभी वगरे को ऊर्जा संरक्षण के प्रति सजग हो जाना चाहिए। जन सामान्य को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि निजी वाहन को वुछ दिन के लिए पेट्रोल व डीजल की जरूरत न पड़े।

दिल्ली दरबार पर भारी पड़ा जमीनी नेता, केरल में सतीशन क्यों बने कांग्रेस का चेहरा

(जीएनएस)।

वीडी सतीशन की जीत ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब केवल हाईकमान आधारित राजनीति के भरोसे नहीं चलना चाहती।

केरल में पाटा ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि जनता और कार्यकताओं के बीच स्वीकार्यता रखने वाला नेता ही सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश होता है। यही कारण है कि इस बार दिल्ली की ताकत पर जमीन की हकीकत भारी पड़ गई।

दिल्ली दरबार पर भारी पड़ा जमीनी नेता, केरल में सतीशन क्यों बने कांग्रेस का चेहरा केरल की राजनीति में इस बार सिर्प सरकार नहीं बदली, कांग्रेस की अंदरूनी ताकत का नक्शा भी बदल गया। दस वर्षो बाद सत्ता में लौटी यूनाइटेड डेमोव्रेटिक प्रंट सरकार ने जब वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुना तो यह पैसला केवल एक व्यत्ति को वुर्सा सौंपने का नहीं था, बल्कि कांग्रेस के भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कदम बन गया। चुनाव नतीजे आने के बाद लगभग दस दिनों तक दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक जिस तरह की खींचतान चली, उसने साफ कर दिया था कि यह लड़ाई सिर्प मुख्यमंत्री पद की नहीं, बल्कि कांग्रेस में दिल्ली मॉडल बनाम जमीनी मॉडल की थी।

आखिरकार पाटा ने संगठन महासचिव और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले केसी वेणुगोपाल के बजाय उस नेता पर भरोसा जताया, जिसने पांच वर्षो तक विपक्ष में रहकर कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया।

2026 के विधानसभा चुनाव में 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें हासिल कीं, जबकि उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतीं। एलडीएफ गठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। 2021 में कांग्रेस नीत यूडीएफ को सिर्प 41 सीटें मिली थीं और एलडीएफ 99 सीटों के साथ सत्ता में लौटा था।

यानी पांच वर्षो में कांग्रेस ने 22 सीटों की सीधी बढ़त दर्ज की, जबकि वाम मोर्चा 64 सीटें खो बैठा। यही आंकड़े बताते हैं कि यह जीत किसी सामान्य सत्ता विरोधी लहर का परिणाम नहीं थी, बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में वीडी सतीशन की बनाई राजनीतिक रणनीति का असर थी।

दरअसल, 2021 की हार कांग्रेस के लिए केवल चुनावी पराजय नहीं थी, बल्कि संगठनात्मक संकट भी थी। पाटा के भीतर वर्षो से चल रही ए ग्रुप और आई ग्रुप की राजनीति ने कार्यकताओं को थका दिया था।

ओमन चांडी और के. करुणाकरण के दौर से चली आ रही गुटबाजी ने कांग्रेस को जनता से दूर कर दिया था। ऐसे समय में राहुल गांधी ने रमेश चेन्निथला की जगह वीडी सतीशन को विपक्ष का नेता बनाया। उस समय यह पैसला जोखिम भरा माना गया, क्योंकि सतीशन के पास न दिल्ली की लॉबी थी और न ही संगठन पर वैसी पकड़, जैसी केसी वेणुगोपाल के पास मानी जाती थी। लेकिन पांच साल बाद वही पैसला कांग्रेस के पुनजावन की सबसे बड़ी वजह बन गया। सतीशन ने विपक्ष का नेता बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस की चुनावी राजनीति की शैली बदली। उन्होंने साफ कहा कि टिकट वितरण में गुटीय वफादारी नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता देखी जाएगी। इसका असर स्थानीय निकाय चुनावों में दिखाई दिया।

दिसंबर 2025 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ ने 941 पंचायतों में से 505 पर जीत हासिल की। 87 नगर पालिकाओं में से 54 यूडीएफ के खाते में गईं।

14 जिला पंचायतों में से 7 पर कब्जा हुआ, जबकि 6 में से 4 नगर

निगमों में कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली। इन नतीजों ने पहली बार यह संकेत दिया कि एलडीएफ की पकड़ कमजोर हो रही है और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है।

सतीशन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी डेटा आधारित राजनीति रही।

विधानसभा में उन्होंने सिर्प राजनीतिक आरोप नहीं लगाए, बल्कि सरकारी आंकड़ों के जरिए पिनाराई विजयन सरकार को घेरा।

केरल में बेरोजगारी दर, राज्य का बढ़ता कर्ज, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों को उन्होंने लगातार उठाया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, 2025 में केरल की शहरी बेरोजगारी दर 18ट्ट के करीब पहुंच गई थी, जबकि युवाओं में यह आंकड़ा 30ट्ट से अधिक था।

पिछले पांच वर्षो में लगभग 18 लाख युवा रोजगार और शिक्षा के लिए राज्य से बाहर गए। सतीशन ने इन आंकड़ों को लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाया और कांग्रेस को भविष्य की अर्थव्यवस्था की भाषा बोलने वाली पाटा के रूप में पेश किया। केरल की सामाजिक संरचना को समझे बिना इस पैसले को समझना मुश्किल है। राज्य की राजनीति में नायर, ईसाई और मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल दोनों नायर समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में लगभग 14 से 15 प्रतिशत मानी जाती है।

लेकिन फर्व यह रहा कि सतीशन लगातार नायर बहुल परवूर सीट से पांच बार चुनाव जीत चुके हैं।

2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। इससे उनकी जमीनी पकड़ मजबूत मानी जाती है। दूसरी ओर, वेणुगोपाल लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सव्रिय रहे और राज्य की सव्रिय राजनीति से उनकी दूरी बढ़ती गई।

कांग्रेस के लिए सबसे अहम बात यह थी कि सतीशन को अल्पसंख्यक समुदायों का भी व्यापक समर्थन हासिल था। केरल की लगभग 26ट्ट आबादी मुस्लिम और करीब 18ट्ट ईसाई है।

यूडीएफ की सबसे बड़ी सहयोगी आईयूएमएल शुरू से सतीशन के पक्ष में थी।

मुस्लिम लीग को यह आशंका थी कि अगर दिल्ली से कोई नेता मुख्यमंत्री बनकर आता है तो गठबंधन के भीतर संतुलन बिगड़ सकता है। चर्च समूहों के बीच भी सतीशन की छवि एक ऐसे नेता की रही, जो वैचारिक रूप से उदार हैं लेकिन धरमिक तुष्टिकरण की खुली राजनीति नहीं करते। यही वजह रही कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें सर्वस्वीकार्य चेहरा माना। केसी वेणुगोपाल की दावेदारी के सामने सबसे बड़ा संकट उनकी राजनीतिक स्थिति थी। वे लोकसभा सांसद हैं और पाटा महासचिव भी। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पहले संसद सदस्यता छोड़नी पड़ती।

इसके बाद किसी विधायक की सीट खाली कराकर उन्हें छह महीने के भीतर विधानसभा पहुंचाना पड़ता। यानी एक लोकसभा और एक विधानसभा उपचुनाव का अतिरित्त जोखिम पैदा होता। कांग्रेस पहले ही जानती थी कि सत्ता में आने के बाद शुरूआती महीनों में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता का संदेश नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही कारण है कि अंतिम समय में हाईकमान ने कम जोखिम वाले विकल्प पर भरोसा जताया। इस पैसले का राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश भी बड़ा है।

कांग्रेस लंबे समय से इस आलोचना का सामना करती रही है कि पाटा में पैसले सिर्प दिल्ली दरबार के आधार पर होते हैं।

लेकिन केरल में पाटा ने पहली बार साफ संकेत दिया कि अब चुनाव जिताने वाले क्षेत्रीय नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सतीशन की ताजपोशी कांग्रेस के भीतर पीढ़ीगत बदलाव का भी प्रतीक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल प्रमुख चेहरों केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशन में सतीशन को अपेक्षावृत युवा और नई पीढ़ी के नेता के तौर पर देखा गया। उनका पूरा राजनीतिक अभियान नई कांग्रेस की अवधारणा पर आधारित था। भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी इस पैसले के पीछे एक बड़ा कारण रहा।

सतीशन इस राजनीतिक संतुलन में फिट बैठते हैं। उनकी छवि आव्रामक सांप्रदायिक राजनीति से दूर लेकिन सांस्वृतिक रूप से जुड़ी हुई मानी जाती है।

अब सबसे बड़ी चुनौती वादों को जमीन पर उतारने की होगी। केरल इस समय लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। राज्य में निजी निवेश की रफ्तार धीमी है और युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। सतीशन ने चुनाव के दौरान ग्लोबल जॉब नेटवर्व, शिक्षा सुधार और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया था। अगर वे इन मोर्चो पर ठोस परिणाम देते हैं तो कांग्रेस सिर्प केरल में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया राजनीतिक मॉडल पेश कर सकती है। वीडी सतीशन की जीत ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब केवल हाईकमान आधारित राजनीति के भरोसे नहीं चलना चाहती। केरल में पाटा ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि जनता और कार्यकताओं के बीच स्वीकार्यता रखने वाला नेता ही सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश होता है। यही कारण है कि इस बार दिल्ली की ताकत पर जमीन की हकीकत भारी पड़ गई।

केरलम में 26 मई को दस्तक देगा मानसून! आईएमडी ने बताई तारीख, आपके शहर में कब होगी बारिश?

(जीएनएस)।

भारत में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी (व्टऊ) ने मानसून 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई 2026 को केरल पहुंचने की संभावना है, हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि डेट आगे-पीछे हो सकती है,अनुमान है कि ये 22 मई से 30 मई के बीच कभी भी केरल में दस्तक दे सकता है।

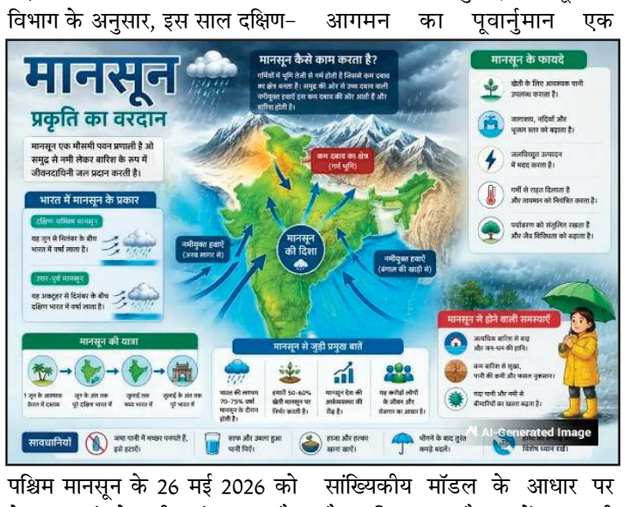

आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून हर साल 1 जून को केरल पहुंचता है। ऐसे में यदि मानसून 26 मई को आता है तो इसे सामान्य से पहले माना जाएगा। इससे किसानों, कृषि क्षेत्र और जल संकट से जूझ रहे राज्यों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस खबर के सामने आने के बाद बाराबंकी के किसान राम चरण दास ने कहा कि 'ये वाकई अच्छी खबर है।'

क्टऊ के अनुसार, मानसून के आगमन का पूवार्नुमान एक सांख्यिकीय मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें समुद्र की सतह के तापमान, वायुमंडलीय दबाव, हवा की दिशा और हिंद महासागर की जलवायु स्थितियों जैसे कई कारकों का अध्ययन किया जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रारंभिक अनुमान है और आगे मौसम की परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव संभव है।

मानसून का जल्दी आना सुखद है: मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिशए, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश (लखनऊ) का मानना है कि 'अगर मानसून समय से पहले आता है और इसकी प्रगति सामान्य रहती है, तो देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से जल्दी राहत मिल सकती है, साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई भी समय पर शुरू हो सकेगी। धान, कपास, सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों के लिए समय पर बारिश बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।'

मानसून के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है, मोहम्मद दानिश के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रही मौसमी परिस्थितियां मानसून को अनुकूल बना रही हैं। पिछले कुछ वर्षो में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। कभी अत्यधिक बारिश तो कभी लंबे सूखे जैसी स्थितियां सामने आई हैं। ऐसे में इस बार मानसून के समय से पहले आने की खबर काफी अहम है।

केरल में पहले आता है मानसून, केरल में मानसून की दस्तक को भारत में बारिश के मौसम की औपचारिक शुरूआत माना जाता है। इसके बाद मानसून धीरे-धीरे कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों, महाराष्ट्र और फिर उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। सामान्य परिस्थितियों में जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेता है।

मानसून क्या है? मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है, जो साल के एक निश्चित समय पर अपनी दिशा बदलती है और भारी बारिश लेकर आती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण-पश्चिम मानसून माना जाता है, जो जून से सितंबर तक देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा करता है। यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आता है, जिससे पूरे देश में बारिश होती है।

कृषि प्रधान देश के लिए मानसून बेहद अहमए भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मानसून बेहद अहम है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। अगर मानसून सामान्य रहे तो फसल अच्छी होती है, जलाशय भरते हैं और बिजली उत्पादन से लेकर पीने के पानी तक की जरूरतें पूरी होती हैं। भारत की लगभग 50-60 प्रतिशत खेती आज भी बारिश पर निर्भर मानी जाती है। ऐसे में मानसून देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जैसा है। मानसून कमजोर होने पर सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, इसके कारण खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, नदियां, तालाब और बांध भरते हैं, भूजल स्तर बढ़ता है, गर्मी से राहत मिलती है, बिजली उत्पादन में मदद मिलती है और पेड़-पौधों और पर्यावरण को जीवन मिलता है। अगर मानसून कमजोर पड़ जाए तो सूखा, पानी की कमी और महंगाई जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं अत्यधिक बारिश बाढ़ और नुकसान का कारण बनती है।

मैदान से दूर रहने के बावजूद गूंज रहा है माही का नाम

आईपीएल 2026 का सीजन अपने रोमांचक मोड़ पर है। लेकिन मैदान पर फैंस को थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी की कमी खल रही है। कॉफ इंजरी के कारण धोनी इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। भले ही धोनी डगआउट में बैठकर अपनी टीम का मार्गदर्शन कर रहे हों, लेकिन उनके संन्यास के सालों बाद भी वनडे क्रिकेट का एक ऐसा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, जिसके करीब पहुंचना भी आज के बल्लेबाजों के लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा है।

धोनी के नाम दर्ज है अनोखा रिकॉर्ड

वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एमएस धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो 84 बार नॉट आउट पवेलियन लौटे हैं। एक फिनिशर के तौर पर धोनी ने मैच को अपने तरीके से खत्म करने में महारथ हासिल की। क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि धोनी का यह रिकॉर्ड किसी भी खिलाड़ी के लिए तोड़ना

आसान नहीं होगा।

धोनी के इस रिकॉर्ड की खासियत यह नहीं है कि वे अंत तक टिके रहे, बल्कि यह है कि वे दबाव वाले मौकों पर टीम को जीत दिलाकर लौटे। अक्सर जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करती थी तो धोनी अंतिम ओवर तक खेल को ले जाते थे। उनका मानना था कि गेंदबाज से ज्यादा दबाव बल्लेबाज पर होता है, लेकिन वे खुद इतने शांत रहते थे कि विपक्षी कप्तान के पसीने छूट जाते थे।

क्या बदल गया है क्रिकेट खेलने का अंदाज

आज के दौर में वनडे क्रिकेट खेलने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। आजकल के बल्लेबाज स्ट्राइक रेट बढ़ाने के चक्कर में बड़े शॉट्स खेलते हैं और जल्दी विकेट गंवा देते हैं। आधुनिक क्रिकेट में धोनी जैसा धैर्य और क्रीज पर टिके रहने की स्थिरता कम ही खिलाड़ियों में नजर आती है। धोनी अक्सर नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करते थे, जहां नॉट आउट रहने की संभावना तो होती है लेकिन मैच जिताने की जिम्मेदारी सबसे कठिन होती है। आज के फिनिशर्स अंत तक टिकने के बजाय कैमियो (छोटी और तेज पारी) खेलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

आईपीएल 2026 के लापता सितारे, करोड़ों रुपये लेकर भी धोनी सहित ये दिग्गज अब तक नहीं खेले एक भी मैच!

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है, लेकिन कई क्रिकेट फैंस के लिए यह सीजन थोड़ा फीका साबित हो रहा है। टूनार्मेंट के कुछ सबसे बड़े सितारों का मैदान से दूर रहना फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। एमएस धोनी से लेकर मथीशा पथिराना तक कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो या तो इंजरी के शिकार हैं या टीम कॉम्बिनेशन की वजह से अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं।

धोनी अब तक नहीं खेल पाए हैं एक भी मैच (क्छछ 2026 छंशी२३ ठी६२)

क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि ये मैच विनर अपनी टीमों की किस्मत बदलेंगे, लेकिन फिलहाल ये केवल डगआउट की शोभा बढ़ा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े पोस्टर बॉय एमएस धोनी इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेल सके हैं। 44 वर्षीय धोनी अपनी पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं। हालांकि वह टीम के साथ अधिकतर मैच में सफर कर रहे हैं और मेंटॉर की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन उनके हाथों में दस्ताने और बल्ला न देखकर फैंस काफी मायूस हैं।

मथीशा पथिराना का इंतजार कर रहे हैं फैंस, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, जिन्हें डेथ ओवर का सबसे घातक हथियार माना जाता है, हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण इस सीजन में अब तक एक्शन से बाहर हैं। पिछले सीजन में डेथ ओवर्स में कहर बरपाने वाला यह गेंदबाज इस है, जिसका फायदा विपक्षी टीमें उठा रही हैं।

पृथ्वी को मिली किस गलती की सजा? दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल 2026 अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। कभी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाने वाले बार केकेआर की प्लेइंग-का हिस्सा नहीं बन सके हैं। पथिराना की गैरमौजूदगी में केकेआर की डेथ बॉलिंग काफी कमजोर नजर आ रही शॉ इस पूरे सीजन में एक-एक मौके के लिए तरस गए हैं। मैनेजमेंट ने उन्हें एक भी मैच की प्लेइंग-क में जगह नहीं दी है। उनकी जगह टीम ने युवाओं और अन्य विदेशी विकल्पों पर भरोसा जताया है।

रचिन रविंद्र को नहीं मिला मौका, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र ने पिछले आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से लोहा मनवाया था। लेकिन इस बार वह बेंच गरम कर रहे हैं। केकेआर के पास विदेशी खिलाड़ियों की भरमार और टॉप ऑर्डर में फिन एलन के साथ कैमरुन ग्रीन की स्थिरता के कारण रचिन को मौका नहीं मिल पा रहा है। कई विदेशी खिलाड़ी के बाहर होने के बाद भी टीम में उनकी जगह नहीं बन सकी है।

सिर्फ चेन्नई और केकेआर ही नहीं अन्य टीमों में भी कई बड़े नाम मौके का इंतजार कर रहे हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका के कुछ तेज गेंदबाज और भारत के घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे शामिल हैं, जो इम्पैक्ट प्लेयर नियम के बावजूद प्लेइंग-क में जगह नहीं बना पाए हैं।

विचारधारा, राजनीति और इतिहास के सवालों को बेबाकी से उठाती है 'आखिरी सवाल'

मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र विक्की (नमाशी चक्रवर्ती) अपने प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी (संजय दत्त) से पीएचडी थीसिस को लेकर तीखी बहस करता है। प्रोफेसर ने उसकी आरएसएस पर आधारित रिसर्च को अस्वीकार कर दिया है। प्रोफेसर नाडकर्णी आरएसएस की विचारधारा - व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण - को विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्की उन्हें संगठन का समर्थक बताते हुए सवाल खड़े करता है। बहस धीरे-धीरे इतना उग्र रूप ले लेती है कि प्रोफेसर गुस्से में विक्की को थप्पड़ मार देते हैं। इस घटना को प्रोफेसर पल्लवी मेनन (समीरा रेड्डी) अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती हैं। देखते ही देखते यह मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। इसके बाद विक्की प्रोफेसर के सामने 5 बड़े सवाल रखता है और कहता है कि यदि उन्हें संतोषजनक जवाब मिल गया तो वह अपनी थीसिस वापस ले लेगा। विक्की की मित्र सारा (त्रिधा चौधरी) उसे आगाह करती है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस पूरे विवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं।

क ॉलेज ऑडिटोरियम में विक्की पहला सवाल उठाता है कि आखिर आरएसएस पर सरकार ने तीन बार प्रतिबंध क्यों लगाया था? इसके बाद सवाल-जवाब और विचारधाराओं की बहस का सिलसिला शुरू होता है, जो धीरे-धीरे राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की सुर्खियाँ बन जाता है। न्यूज एंकर आदित्य (अमित साध) इस मुद्दे को प्राइम टाइम डिबेट में बदल देता है, जबकि चैनल की शो डायरेक्टर काव्या रावत (नीतू चंद्रा) भी इस पूरे विवाद में गहरी रुचि दिखाती हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर नाडकर्णी की पत्नी प्रभा (मृणाल कुलकर्णी) उन्हें मानसिक रूप से इस चुनौतीपूर्ण बहस के लिए तैयार करती हैं। फिल्म एक साधारण अकादमिक विवाद को राष्ट्रीय स्तर की वैचारिक बहस में तब्दील कर देती है। कहानी में आरएसएस समर्थक सोच, विरोधी विचारधारा और मीडिया के प्रभाव को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

आखिरी सवाल में कैसी रही कलाकारों की परफॉर्मेंस? प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी के रोल में संजय दत्त बेहद संयमित और प्रभावशाली नजर आते हैं। उन्होंने अपने अभिनय में गंभीरता और भावनात्मक गहराई का बेहतरीन मेल दिखाया है। उनके संवाद और व्यक्तित्व फि ल्म को मजबूत आधार देते हैं। विक्की के किरदार में नमाशी चक्रवर्ती ने गुस्से, बेचैनी और सवालों से भरे युवा की मानसिकता को प्रभावी ढंग से पर्दे पर उतारा है। यह उनके करियर की सबसे सशक्त प्रस्तुतियों में से एक मानी जा सकती है। अमित साध एक आक्रामक और स्मार्ट न्यूज एंकर के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। वहीं नीतू चंद्रा चैनल की संपादक के किरदार में सधी हुई दिखाई देती हैं। समीरा रेड्डी अपने नेगेटिव शेड्स वाले किरदार से दर्शकों को प्रभावित करती हैं। त्रिधा चौधरी और मृणाल कुलकर्णी भी अपने किरदारों के जरिए कहानी को भावनात्मक मजबूती प्रदान करती हैं।

निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग ने इतने संवेदनशील और विवादास्पद विषय को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने तथ्यों और सिनेमाई नाटकीयता के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखा है। फिल्म का पहला भाग छात्र और प्रोफेसर के बीच विचारों की टकराहट को दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ाता है। संवाद असरदार हैं और कई दृश्य लंबे समय तक दर्शकों के जहन में बने रहते हैं।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

'मोदी जी, योगी जी आप अपनी सुरक्षा कम मत करिए', रवि किशन ने दुश्मन देशों का जताया डर! कहा- मैं साइकिल से चलूंगा

(जीएनएस)।

गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात की है।

गोरखपुरः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा कम किए जाने के मसले पर एक खास अपील की है। इसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, सीएम योगी शुक्रवार को गोरखपुर के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे थे। सांसद रवि किशन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो गाड़ी पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसा कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमत के कारण लोगों को संदेश देने के लिए इस प्रकार इन नेताओं ने सुरक्षा में कमी की है, लेकिन यह खतरनाक है।

गोरखपुर सांसद रवि किशन ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा आवश्यक है। हम लोगों ने काफिला लेकर चलना बंद कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहे हैं। आप कहेंगे तो हम ईवी छोड़कर साइकिल से चल लेंगे, लेकिन

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना काफिला काम नहीं करना चाहिए। उनकी सुरक्षा अधिक जरूरी है।

रवि किशन ने इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि पूरी दुनिया आप पर नजर रखती है। इसमें कई आतंकवादी संगठन और हमारे दुश्मन पड़ोसी देश भी शामिल हैं। आप कृपया अपनी सुरक्षा कम नहीं करें। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है। रवि किशन के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद यूजर्स ने भी उनके समर्थन में बातें कहीं।

गोरखपुर में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध का संकट झेल रहा है। ईंधन की आपूर्ति बाधित हो गई है। दुनिया के लगभग सभी देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। अमेरिका ने तो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम चार गुना तक बढ़ा दिए हैं। यूरोपीय देशों की हालत खराब है। पाकिस्तान किसी प्रकार समय काट रहा है। अरब देश अंधकार में रहने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि 12 फरवरी से लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है।

सीएम योगी ने कहा कि जनता पर अधिक बोझ न आए, इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था की है। पीएम मोदी ने इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए लोगों से विदेश न घूमने जाने और सोना न खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री की मंशा भारत का पैसा भारत में रहने की है। इसलिए हमें अपने प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करना चाहिए।

गोरखपुर में भी अब होंगे आईपीएल के मैच, सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि गोरखपुर को हर खेल सुविधा से समृद्ध करना चाहते हैं। रामगढ़ ताल वाटर स्पोर्ट्स के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। अब बारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 16 मई को गोरखपुर की उपलब्धियों की श्रृंखला में स्वर्णाक्षरों जड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिहाज से गोरखपुर का नाम वैश्विक स्तर पर उल्लिखित कराने तथा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। करीब 393 करोड़ रुपये की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे।

गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन की तरफ से ताल नदोर

में उपलब्ध कराई गई जमीन पर 24 दिसंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

औपचारिक शिलान्यास होने से पहले सरकार की तरफ से जारी परियोजना लागत की प्रथम किश्त 63.39 करोड़ रुपये से काम आगे बढ़ रहा है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड एक (भवन) के अनुसार अब तक करीब सात प्रतिशत काम हुआ है। स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।

गोरखपुर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ क्षेत्रफल में आकार लेगा। 30 हजार दर्शक क्षमता का यह स्टेडियम 'ग्राउंड प्लस टू फ्लोर' के हिसाब से बनेगा। मेन ग्राउंड पर खिलाड़ियों के लिए सात प्लेइंग पिच और चार प्रैक्टिस पिच होगी। यहां स्टेडियम के पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड में प्रत्येक में 14,490 दर्शक बैठ सकेंगे। नार्थ पैवेलियन 208 वीआईपी व 382 मीडियाकर्मियों और साउथ पैवेलियन 1708 वीवीआईपी व वीआईपी के लिए होगा। रात्रिकालीन मैच भी हो सकें, इसके लिए मेन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानक के चार हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था रहेगी। यहां क्रिकेट के अलावा अन्य बड़े आयोजन भी होंगे।

ताल नदोर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतरीन जगह पर है। गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग फोरलेन से जुड़ा यह स्थान, गोरखपुर एयरपोर्ट से करीब 24 किमी की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से करीब 20 किमी है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए यहां पहुंचना काफी सुगम होगा।

गोरखपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में देश की शीर्ष पेट्रोलियम कंपनियां अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड से कुल 100 करोड़ रुपये देंगी। एमओयू के बाद धनराशि आवंटन प्रक्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड साठ करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम तीस करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दस करोड़ रुपये देगी।

एसएस मोता सिंह स्कूल मामले में सियासी विवाद गहराया, ट्रस्ट और फाइल गायब होने पर आम आदमी पार्टी का आरोप

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जिस एसएस मोता सिंह स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका राजनीतिक संबंध होने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री आशीष सूद की गलत बयानी पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में एसएस मोता सिंह स्कूल की फाइल गायब हो गई है।

आशीष सूद बताएं कि सरकार क्या छिपाना चाहती है? ट्रस्ट में आने-जाने वाले सदस्यों की सारी जानकारी सरकार के सब रजिस्ट्रार को दी जाती है। वह फाइल कैसे गायब हो गई? उन्होंने पूछा कि अगर स्कूल का कोई राजनीति संबंध नहीं है तो फिर अमरजीत सिंह बब्बू ने फेसबुक पर ट्रस्टी बनाने का सारा श्रेय मंत्री प्रवेश वर्मा को देते हुए उन्हें धन्यवाद क्यों किया?

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्कूल के ट्रस्ट में अमरजीत सिंह के अलावा डॉ. वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, स्वाति गर्ग और मनीष गुप्ता नए ट्रस्टी बने हैं। फेसबुक पर पोस्ट करने से अमरजीत सिंह बब्बू के बारे कुछ जानकारी मिल गई, लेकिन बाकी तीन लोग कौन हैं?

बच्ची के पैरेंट्स का कहना है कि वे जब भी थाने गए, तो स्कूल के जनकपुरी ब्रांच के मैनेजर मनजीत सिंह ओलख वहां मिले, जो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के करीबी हैं और साथ में दोनों की फोटो भी है। उन्होंने कहा कि आज तीन साल की रेप पीड़ित बच्ची तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। इसके बावजूद स्कूल मैनेजमेंट को क्यों बचाया जा रहा है? उन्होंने आशीष सूद से स्कूल की फाइल सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि स्कूल का राजनीतिक संबंध है या नहीं है।

शुक्रवार को "आप" मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एसएस मोटा सिंह पब्लिक स्कूल में जिस तीन साल की बच्ची से स्कूल के ही एक अधिकारी ने उसके

साथ रेप किया। उस बच्ची को परिजन जब दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले गई, तो रात में करीब सवा दो बजे उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल करने वाली डॉक्टर ने लड़की की मां से कहा था कि बच्ची का हाइमन रप्चर हो गया है, लेकिन बाद में डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट के अंदर इस बात को नहीं लिखा।

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उसके बाद से लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने खाना-पीना बेहद कम कर दिया था और उसे यूरिन पास करने तक में तकलीफ हो रही थी। परिवार ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें भी बच्ची को काफी दिक्कतें बताई गईं।

गुरुवार को उस बच्ची की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मां-बाप के हालात ऐसे हैं कि वे फोन करके पूछ रहे हैं कि अगर पैसे की दिक्कत हुई और सरकार ने पैसे नहीं दिए तो वे क्या करेंगे? हमने परिवार से कहा है कि वे पैसे की चिंता न करें, उन्हें दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और वे बस इलाज कराएं। मगर यह बड़े शर्म की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज स्कूल जाने वाली एक मासूम बच्ची के साथ ऐसे हालात हो गए हैं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी बच्ची की हालत कैसी है यह नहीं पता, लेकिन रात को उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया और वह अभी भी एडमिट है। बच्ची को सीवियर इंफेक्शन बताया गया है और यह इंफेक्शन क्यों होता है, यह सब लोग भली-भांति जानते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अदालत ने आरोपी को कुछ दिन पहले ही बेल दे दी है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहली बार इस मामले पर बोले, जबकि यह उनके अपने क्षेत्र जनकपुरी का एक जाना-माना स्कूल है। यह स्कूल उनके घर से दो मिनट की दूरी पर है, इसलिए वे ऐसा नहीं कह सकते कि वे इस स्कूल को नहीं जानते।

मार्च में आशीष सूद ने खुद इस स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा भजन क्लबिंग वाला एक भव्य कार्यक्रम कराया था। हजारों लोग उसमें आए थे और लाखों या हो सकता है करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए हों। सरकार खर्चा तो बताती नहीं है और विधानसभा में भी नहीं बताती। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आशीष सूद दोनों मौजूद थे। ऐसे किसी अनजान स्कूल के अंदर सरकारें सरकारी खर्च से बड़े-बड़े प्रोग्राम नहीं रखा करतीं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुरुवार को आशीष सूद ने बहुत भद्दी और घटिया बात कही। वे कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज बताएं कि भाजपा के किस नेता और मंत्री ने इस स्कूल में स्टेक्स खरीदे हैं। जब शिक्षा मंत्री भाजपा के हैं, राजस्व मंत्री भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भाजपा की हैं और सब रजिस्ट्रार दफ्तर भी उनका ही है, तो कागज सौरभ भारद्वाज कहां से लाएंगे? कागज तो भाजपा सरकार के पास ही हैं।

सौरभ भारद्वाज ने ट्रस्ट के खेल के बारे में बताते हुए कहा कि पांच-सात आदमियों का एक ट्रस्ट होता है जो स्कूल को चलाता है। एसएस मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट का नाम एसएस मोता सिंह नीला चैरिटेबल ट्रस्ट है। नीला पाकिस्तान के उस गांव का नाम है जहां से इसकी शुरूआत हुई थी।

इस ट्रस्ट के पास करीब 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। पश्चिम विहार में 7 एकड़, जनकपुरी में करीब ढाई एकड़ और 500 गज जमीन अलग से है। स्कूलों के ट्रस्ट का खेल यह होता है कि दो ट्रस्टी रिजाइन करते हैं और दो नए आ जाते हैं। फिर दो और रिजाइन करते हैं और दो नए आ जाते हैं। धीरे-धीरे पुराने ट्रस्टी गायब हो जाते हैं और नए ट्रस्टी आ जाते हैं, जिनमें से एक आदमी चेयरमैन बन जाता है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस तरह 500 करोड़ की संपत्ति कुछ हाथों से दूसरे हाथों में पहुंच जाती है और इसके लिए पैसे का सारा लेनदेन ब्लैक और कैश में होता है।

ऐसे ही कोई फ्री में ट्रस्ट देकर खुद हरिद्वार जाने की बात नहीं कह सकता। इस तरह के ट्रस्टों में जो लेनदेन होता है, वह ब्लैक में होता है। जबकि आदर्श रूप में यह लेनदेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें नॉन प्रॉफिट कहा जाता है।

जनगणना 2027: जम्मू के उपायुक्त ने 17 मई से शुरू होने वाली डिजिटल स्व-गणना में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया

(जीएनएस)।

जम्मू के उपायुक्त राकेश मिन्हास ने निवासियों से 17 मई से शुरू होने वाली जनगणना 2027 के लिए डिजिटल स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लेने का आ'ान किया है। उन्होंने गणनकों के आने पर सत्यापन के लिए परिवारों द्वारा अपनी स्व-गणना आईडी तैयार रखने के महत्व पर जोर दिया, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी और क्षेत्र सत्यापन का समय कम होगा।

डिजिटल स्व-गणना सुविधा 17 मई से 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। मिन्हास, जो जम्मू जिले के लिए प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, ने घोषणा की कि आधिकारिक पोर्टल 17 मई को सुबह 6 बजे लाइव हो जाएगा। नागरिक एक सक्रिय मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार और व्यक्तिगत विवरण भर सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं, और एक अद्वितीय स्व-गणना आईडी (SE ID) प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी वयस्क परिवार का सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग करके प्रक्रिया पूरी कर सकता है। 1 जून से 30 जून तक, प्रशिक्षित गणनक घर-घर जाकर मकानों की सूची बनाने का कार्य करेंगे। इन कार्यों में 33 प्रश्नों वाले एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र करना शामिल होगा, जो घरेलू सुविधाओं, स्वामित्व की स्थिति और अन्य सुविधाओं से संबंधित होंगे।

मिन्हास ने स्पष्ट किया कि स्व-गणना एक अतिरिक्त सुविधा है। जो निवासी डिजिटल प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 जून से 30 जून तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच सरकारी गणनक जिले के सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने उन परिवारों से आग्रह किया जिन्होंने स्व-गणना पूरी कर ली है, वे इन दौरों के दौरान सत्यापन के लिए अपनी रए कऊ तैयार रखें।

सभी गणनकों के पास सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होंगे। मिन्हास ने निवासियों को जानकारी साझा करने से पहले उनकी पहचान सत्यापित करने की सलाह दी। उन्होंने जनगणना कार्यों के बहाने पैसे वसूलने की कोशिश करने वाले धोखेबाजों के खिलाफ भी चेतावनी दी, और दोहराया कि यह पूरी कवायद निःशुल्क है।

दिल्ली-एनसीआर में इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

(जीएनएस)।

दिल्ली-एनसीआर की हवा में घुलता जहर अब सिर्फ एक मौसमीय समस्या नहीं, बल्कि एक बड़ी नीति-क्रांति का कारण बन रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (उअदट) ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए ऐसे कड़े फैसले लिए हैं। जो आने वाले समय में न सिर्फ वाहनों की दुनिया बदल देंगे, बल्कि खेतों से उठने वाले धुएं तक पर सीधी चोट करेंगे। हालांकि दमघोंटू हवा से बचने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू होंगे, जिनका सीधा असर आमजन पर पड़ेगा।

दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल पंपों पर अब सख्त नियम लागू होंगे। 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (ठउफ) में 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' व्यवस्था अनिवार्य होगी। वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (ढवउ) के बिना कोई भी पेट्रोल पंप संचालक ईंधन नहीं देगा। आयोग ने यह कदम लोगों की पीयूसी बनवाने में लापरवाही सुधारने और हर वाहन के लिए प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

प्रदूषण घटाने के लिए कामर्शियल

वाहन बाजार को भी बदला गया है। माल ढुलाई या सवारी ढोने वाले थ्री-व्हीलर (छ5 कैटेगरी) अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगे। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही पंजीकृत किए जाएंगे।

यह बदलाव दिल्ली तक सीमित नहीं। 1 जनवरी 2028 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, सोनीपत जैसे अहम औद्योगिक शहरों में भी यही नियम लागू होगा। अंततः, 1 जनवरी 2029 से पूरे बचे एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही पंजीकृत होंगे, जो प्रदूषण रोकने में सहायक होगा।

सर्दियों में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के खेतों से उठने वाला पराली का धुआं दिल्ली की हवा बिगाड़ देता है। इसके स्थायी समाधान हेतु उअदट ने 15 मई 2026 को 'डायरेक्शन नंबर 99' जारी किया। इसके तहत, तीनों राज्यों को एक कड़ा एक्शन प्लान मिला है, जिसमें 'पराली प्रोटेक्शन फोर्स' का गठन सबसे अहम कदम है।

इस एक्शन प्लान में हर खेत की डिजिटल मैपिंग व जवाबदेह नोडल अधिकारियों की तैनाती भी शामिल है। उअदट का लक्ष्य है कि 2026 के धान कटाई सीजन में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य पर लाया जा सके, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित होगा।

पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सीबीआई ने धर दबोचा

(जीएनएस)।

पेपर लीक मामले में सीबीआई को शुक्रवार को बड़ी कामयाबाी मिली है। सीबीआई ने इस केस के कथित मास्टरमाइंड बताए जा रहे पी.वी. कुलकर्णी को अरेस्‍ ट कर लिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, पीवी कुलकर्णी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे प्रश्नपत्रों तक सीधी पहुंच मिलने की बात सामने आई है।

कुलकर्णी NEET UG परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े होने का फायदा उठाकर पेपर लीक नेटवर्क का हिस्सा बना और छात्रों तक सवाल-पहले ही पहुंचाने में भूमिका निभाई। आइए जानते हैं कौन हैं ये पीवी कुलकर्णी और कैसे पहुंचा इसके पास पेपर?

ठएएळ-वक्ष्2026 ढंस्री१ छीँ

हँड्ग्‍२ ढश ङ४"१ल्ल? कौन हैं पी.वी. कुलकर्णी?

पी.वी. कुलकर्णी पुणे में केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। वे मूल रूप से महाराष्‍ ट्र के लातूर के रहने वाले हैं। सीबीआई के अनुसार, कुलकर्णी का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा व्यवस्था से जुड़ाव था, जिसकी वजह से उन्हें प्रश्नपत्रों तक पहुंच मिलने की आशंका जताई जा रही है।

कैसे खुला पूरा मामला?

जांच एजेंसी के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क तब सामने आया जब आरोपी मनीषा वाघमारे से पूछताछ की गई।

इसके बाद सीबीआई कुलकर्णी तक पहुंची और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

"स्पेशल कोचिंग" चलाकर किया ये खेल

CBI के मुताबिक पीवी कुलकर्णी ने अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे जिसे 14 मई 2026 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसकी मदद से छात्रों को जुटाया था और पुणे स्थित अपने घर पर विशेष कक्षाएं चलाईं। यहां छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और सही जवाब लिखवाए गए, जो बाद में 3 मई 2026 की ठ ए ए ळ - व ॠ परीक्षा के असली पेपर से हूबहू मेल खाते पाए गए।

सीबीआई ने देशभर के कई शहरों में बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान जांच टीमों ने अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। एजेंसी के मुताबिक, इन सभी सामग्रियों की फोरेंसिक और तकनीकी जांच तेजी से की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा सकें।

यह मामला 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसके तुरंत बाद देशभर में विशेष जांच टीमें सक्रिय कर दी गई थीं।

इससे पहले इस केस में जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इनमें से पांच आरोपियों को अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं, गुरुवार को पकड़े गए दो अन्य आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली लाने के उद्देश्य से पुणे की अदालत में ट्रांजिट रिमांड पर पेश किया जा रहा है।

सीबीआई ने जांच में यह भी दावा किया है कि उन्हें केमिस्ट्री पेपर लीक का असली स्रोत और इसमें शामिल बिचौलियों का पता चल गया है।

बताया जा रहा है कि इन लोगों ने मोटी रकम लेकर छात्रों को विशेष कोचिंग कक्षाओं तक पहुंचाया। एजेंसी ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष, व्यापक और पेशेवर तरीके से जांच जारी रहेगी ताकि सभी दोषियों की पहचान की जा सके।

ग्रेटर नोएडा के फर्नीचर मार्केट में कैसे लगी आग? क्या थी वजह? कितना नुकसान?

(जीएनएस)।

ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार (15 मई) शाम को भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि लपटें कई मीटर ऊंची उठ रही थीं और आसमान में घना काला धुआं छा गया। आसपास का इलाका धुंध में छिप गया। आग ने 4-5 फर्नीचर दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों रुपये का फर्नीचर, लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया।

पुलिस और प्रशासन ने तुरंत आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 8 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं। देर शाम तक आग बुझाने और शीतलन का काम जारी रहा। स्थानीय लोगों ने मोबाइल पर जो वीडियो बनाए, उनमें आग की भयावह तस्वीर साफ नजर आ रही है। लपटें छत फोड़कर बाहर निकल रही हैं और चारों तरफ धुएं का गुबार।

शाम के समय जब बाजार में सामान्य चहल-पहल थी, तभी अचानक एक दुकान से आग की लपटें उठनी शुरू हुईं। हवा के कारण आग तेजी से फैली और पास की कई दुकानों तक पहुंच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या विद्युत तंत्र की खराबी बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक जांच अभी जारी है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां रवाना की गईं। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि फर्नीचर मार्केट में लकड़ी, फोम, कपड़े और अन्य

ज्वलनशील सामग्री भरी हुई थी, जो आग को और भड़काती रही। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। दुकानदारों और मजदूरों ने समय रहते खुद को बाहर निकाल लिया।

नुकसान का अनुमान? 4-5 दुकानों को भारी नुकसान। लाखों रुपये का फर्नीचर, रेडीमेड सामान और कच्चा माल जलकर खाक। कई दुकानदारों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। आग की वजह से आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा।

NCR में आग की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? पुरानी इमारतें और विद्युत तंत्रः कई बाजारों और फैक्टरियों में पुरानी वायरिंग है, जो ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट का कारण बनती है। ज्वलनशील सामग्रीः फर्नीचर मार्केट में लकड़ी, पेंट, फोम और कपड़ा, ये सब आग को तेजी से फैलाते हैं। गर्मी का मौसमः मई में तापमान 40 डिग्री के पार होने से बिजली की मांग बढ़ती है और शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ जाती है। सुरक्षा मानकों की अनदेखीः कई दुकानों और फैक्टरियों में फायर सेफ्टी उपकरण (अग्निशमन यंत्र, स्प्रिंकलर, निकास मार्ग) या तो नहीं हैं या काम नहीं कर रहे।

फायर सेफ्टी पर सवाल, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में बार-बार आग की घटनाएं फायर सेफ्टी सिस्टम की कमियों को उजागर करती हैं। क्या बाजारों में नियमित फायर ऑडिट होते हैं? क्या सभी दुकानों में फायर NOC लिया गया है? क्या मजदूरों और दुकानदारों को फायर ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है?

ये सवाल प्रशासन और नगर निगम पर उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और दुकानदारों की प्रतिक्रिया- घटना स्थल पर मौजूद दुकानदारों ने बताया कि आग देखकर उनका खून सूख गया। एक दुकानदार ने कहा, 'सब कुछ जल गया। साल भर का सामान, लाखों का नुकसान। अब क्या करें?' स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की तेजी की तारीफ की, लेकिन कहा कि आग लगने से पहले रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। प्रभावित दुकानदारों को मुआवजे और मदद का आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

2017 के पूर्व दंगा, कर्फ्यू, अराजकता और भ्रष्टाचार थी यूपी की पहचान : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्तीनगर में शुक्रवार को आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में विकास बाधित था। बिजली, सड़क और रोजगार नहीं था। किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। व्यापारी गुंडा टैक्स देने को मजबूर था, चिकित्सक भयाक्रांत रहते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। दंगा, कर्फ्यू, अराजकता, व्यवस्था और भ्रष्टाचार ही यूपी की पहचान बन गई थी।

सीएम ने कहा कि आप सबने बदलते भारत, बदलते उत्तर प्रदेश और गोरखपुर को देखा है। 2017 के पहले जब नौनिहाल पैदा होता था तो मां-बाप उसे इंसेफेलाइटिस से बचाने को लेकर चिंतित रहते थे। बच्चे के बड़ा होने पर पढ़ाई, नौजवान होने पर नौकरी और रोजगार की चिंता थी। रोजगार के लिए यूपी से बाहर जाने पर पहचान का संकट था। आज उत्तर प्रदेश में विकास, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी है। आज बेटी, व्यापारी सभी सुरक्षित हैं। यहां इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना आज चल रहा है। गोरखपुर में एम्स संचालित है और पहले खुद बीमार रहा बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज बेहतरीन सुविधाएं दे रहा है। गोरखपुर में हर तरफ फोरलेन की कनेक्टिविटी है। 15 हजार करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50 हजार नौजवानों को अकेले गोरखपुर में नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्धजन से यह आ'ान भी किया कि वह नौजवानों को बताएं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में क्या था और आज क्या बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11-12 वर्ष में बदलता हुआ भारत आज दुनिया के लिए प्रेरणा बना हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है।

यूपी में आयुष्मान योजना में धांधली रोकने के लिए योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 100 अस्पताल निलंबित; सौ का भुगतान रोका

(जीएनएस)।

लखनऊ। योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी चिकित्सालयों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि योजना के लाभार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अस्पतालों की सूचीबद्धता और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया को किया गया और अधिक सख्त

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में इसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

इसी दिशा में अस्पतालों की सूचीबद्धता और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाया गया है। योगी सरकार द्वारा अस्पताल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल (एचईएम) पोर्टल के माध्यम से सूचीबद्ध अस्पतालों का सत्यापन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों के लिए 35 महत्वपूर्ण मानकों को पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इनमें अस्पताल का पंजीकरण प्रमाणपत्र, फायर सेफ्टी एनओसी, आवश्यक

इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता, एचएफआर पंजीकरण सहित अन्य जरूरी दस्तावेज और व्यवस्थाएं शामिल हैं।

सीईओ ने बताया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसी की ओर से ई-मेल, दूरभाष, संदेश, पत्राचार और वर्चुअल बैठकों के माध्यम से अस्पतालों को हर स्तर पर सहायता दी गई। इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि अब तक 95 प्रतिशत से अधिक अस्पताल सफलतापूर्वक एचईएम 2.0 पोर्टल पर माइग्रेट हो चुके हैं। हालांकि, कुछ निजी अस्पतालों ने निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की। योगी सरकार की ओर से उन्हें कई बार अवसर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद करीब 200 निजी चिकित्सालयों ने मानकों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी नहीं की।

इनमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फरुर्खाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, सुल्तानपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, जालौन, मिजार्पुर, अंबेडकरनगर, रामपुर और सोनभद्र सहित कई जिलों के अस्पताल शामिल हैं।

100 निजी अस्पतालों का रोका गया भुगतान

सीएम योगी के निर्देश पर ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है, जबकि करीब 100 अन्य अस्पतालों को योजना से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को केवल मानक आधारित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं ही प्राप्त हों।

बता दें कि योगी सरकार ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को एनएबीएच गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर पर अस्पतालों की नियमित ऑडिट और मॉनिटरिंग भी कराई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को समय रहते रोका जा सके। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर भी विशेष जोर दे रही है। अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से मरीजों के निस्तारण को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एबीडीएम सक्षम एचएमआईएस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर) प्रणाली को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इससे मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और इलाज की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तेज होगी। राज्य स्तर से अस्पतालों को पोर्टल संचालन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ऐसे मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिनमें चिकित्सकों की डिग्री अथवा विवरण के अनुचित उपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ की बड़ी आबादी में 15 वर्ष में सिर्फ 47 सीएनजी पंप, डीजल-पेट्रोल की खपत कम होना काफी मुश्किल

(जीएनएस)।

लखनऊ। भारत सरकार के आ'ान पर योगी आदित्यनाथ सरकार डीजल-पेट्रोल की खपत कम करने के लिए तमाम प्रयास कर प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को इसका कोई अपेक्षित विकल्प नहीं मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी नहीं दिख रही है।

लखनऊ की ही बात करें तो यहां पर डेढ़ दशक में केवल 47 पंपों पर ही सीएनजी उपलब्ध हो पाई है। हर जगह पर सीएनजी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लोग सीएनजी वाहन लेने से कतरा रहे हैं। यही हाल इवी चार्जंग को लेकर भी है। ग्रीन गैस लखनऊ के अलावा पांच शहरों में सीएनजी की आपूर्ति करती है। वर्ष 2010 में लखनऊ में सीएनजी की आपूर्ति शुरू हुई थी, तब कहा गया था कि अगले पांच वर्षों में सीएनजी का विस्तार शहर के कोने कोने में होगा।

ग्रीन गैस कंपनी 2010 से लेकर अब तक केवल 47 पंपों तक ही सीएनजी पहुंचा पाई है, खुद कंपनी

अब तक अपने केवल सात मदर स्टेशन ही खोल सकी है। इनमें वृंदावन में दो, ट्रांसपोर्टनगर, रतनखंड, गोतमतीनगर, अमौसी और दुबग्गा में एक-एक पंप है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी की लापरवाही से इनकार नही किया जा सकता लेकिन एनओसी आदि की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वर्षों लगते हैं। दुबग्गा पंप का हवाला देते हुए उनका कहना है कि पांच वर्ष से अधिक समय केवल इस पंप की सरकारी एनओसी लेने में लग गया।

लखनऊ में सीएनजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके सापेक्ष गैस की उपलब्धता नहीं है। जानकीपुरम के सुनील सिंह तोमर का कहना है कि उनके पास डीजल वाहन है, इस बार जब से किल्लत शुरू हुई कई बार सीएनजी वाहन खरीदने की सलाह दी, लेकिन जिस तरह जाए सीएनजी के लिए लाइन लग रही हैं उसे देखकर हिम्मत नहीं जुटा सका।

चार्जिंग का नेटवर्क भी व्यापक नहीं

सीएनजी की तरह ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी बेहतर नहीं है। यही कारण है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन भी लेने से लोग कतराते हैं। कंपनियों का दावा था के प्रत्येक दो से तीन किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। पंप के अलावा सार्वजनिक स्थानों, माल, अस्पताल और अन्य प्रतिष्ठानों में चार्जिंग की सुविधा मिलेगी लेकिन अब तक उस दिशा में भी तेजी से काम होता नही दिख रहा।

तहजीब के शहर में बजा टेक्नोलॉजी का डंका, लखनऊ में 'एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव' में यूपी ने दिखाया ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का रोडमैप

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक छवि को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे बड़े 'टेक्नोलॉजी और एआई इनोवेशन हब' के रूप में नई पहचान बना रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नवाबों के शहर लखनऊ में 'एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026' का भव्य आयोजन किया गया, जहाँ देशभर से आए 50 से अधिक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और प्रशासकों ने उत्तर प्रदेश के डिजिटल कायाकल्प पर मंथन किया। यह कॉन्क्लेव केवल एक चर्चा का मंच नहीं, बल्कि यूपी को तकनीक के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कॉन्क्लेव के दौरान 'द एआई-पावर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर' विषय पर आयोजित विशेष वर्कशॉप में डॉ. सुबी चतुर्वेदी (संस्थापक, ठक्लक्ळ)

ने भविष्य की गवर्नेंस का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ अब केवल तहजीब का केंद्र नहीं, बल्कि नवाचार का सबसे उपयुक्त केंद्र बनकर उभरा है। इनमोबी जैसी डीपटेक कंपनियों के आगमन और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते प्रदेश में रिसर्च, टैलेंट और आंत्रप्रेन्योरशिप का एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश को भारत की डिजिटल शक्ति का केंद्र बना देगा।

योगी सरकार ने एआई की शक्ति को समझते हुए लखनऊ की वृंदावन योजना में ₹368 करोड़ की लागत से देश की पहली 'एआई सिटी' (अक ड्ड३८) को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही, 'यूपी एआई मिशन' के लिए ₹225 करोड़ का विशेष बजट आवंटित किया गया है, जो राज्य की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देगा। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह के अनुसार, यह डिजिटल क्रांति उत्तर प्रदेश के 'ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' के लक्ष्य को हासिल करने में गेम-चेंजर साबित होगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में तीन बच्चों का कराया अन्नप्राशन संस्कार, अपने हाथों से खिलाई खीर

(जीएनएस)।

महाराजगंज। नौतनवा में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में उस समय भावुक और आत्मीय माहौल बन गया, जब मुख्यमंत्री ने छह माह के तीन मासूम बच्चों का पारंपरिक अन्नप्राशन संस्कार कराया।

मंच पर मुख्यमंत्री ने उमर सद्दाम, सानवी और प्रशंसा को गोद में लेकर अपने हाथों से खीर खिलाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री के स्नेहपूर्ण व्यवहार को देखकर कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

अन्नप्राशन संस्कार के दौरान

बच्चों के स्वजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि स्वस्थ और सुरक्षित बचपन ही मजबूत समाज की नींव होता है। उन्होंने माताओं से बच्चों के पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की।

कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और अभिभावकों ने इस पहल को बेहद सराहनीय बताया। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकताओं ने बच्चों और माताओं की देखभाल से जुड़ी व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई।

इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरन शर्मा, सुमन शर्मा, कंवलजीत, बंदना, ममता, माया और गीता समेत बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री के हाथों अन्नप्राशन संस्कार होने से बच्चों के स्वजन ने इसे अपने जीवन का यादगार पल बताया।

पिछड़े वर्ग को त्वरित न्याय दिलाने में जुटी योगी सरकार, 87% से ज्यादा शिकायतों का किया निस्तारण

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के संकल्प के साथ सभी वर्गों को न्याय दिला रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित निस्तारण कर रहा है. आयोग साल 2024 से अप्रैल 2026 तक आई कुल शिकायतों में से करीब 87 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर चुका है. इस तरह आयोग ने योगी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए न केवल बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निस्तारण किया है, बल्कि नई शिकायतों पर भी समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की है.

87 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का हुआ निस्तारण

दरअसल योगी सरकार की प्राथमिकताओं में पिछड़ा वर्ग के लोगों

की समस्याओं का त्वरित समाधान, शिकायतों की सुनवाई और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई शामिल है. इसी क्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सक्रियता से बड़ी संख्या में लोगों को न्याय मिला है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 से अप्रैल 2026 तक कुल 3394 शिकायतें आई थीं. इनमें से 2962 मामलों की सुनवाई और कार्यवाही के बाद निस्तारण किया जा चुका है. इस तरह करीब 87 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.

छात्र-छात्राएं भी छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर आयोग से मदद मांगते हैं. साथ ही पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए भी लोग आयोग में प्रत्यावेदन देते हैं. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूची-एक में जातियों के सम्मिलन, निष्कासन और संशोधन से संबंधित कुल 324 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए.

इनमें से 307 मामलों का सुनवाई और कार्यवाही के बाद निस्तारण किया जा चुका है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि पीड़ित लोगों को वास्तविक राहत पहुंचाना है.

लखनऊ जंक्शन पर गिरी महिला प्रतीक्षालय की छत, बचे 200 यात्री

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बंद पड़ी कैंटीन की बगैर अनुमति लिए बृहस्पतिवार को दीवार तोड़ने के दौरान एक पिलर गिर गया। इससे महिला प्रतीक्षालय से जुड़ी छत का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया और महिला प्रतीक्षालय व प्रथम तल पर बने एसी वेटिंग रूम के दो सौ यात्रियों में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ जंक्शन पर लगेज स्कैनर के पास पुरानी कैंटीन है। यहां आईआरसीटीसी की रेल आहार कैंटीन चलती थी, जिसे बंद कर दिया गया। दो महीने बाद इसे रेलवे को सौंप दिया गया। कैंटीन के पास यात्री प्रतीक्षालय है तथा प्रथम तल पर एसी प्रतीक्षालय है। दोनों में क्रमशः 90 व 110 यात्री थे। इस हिस्से को विस्तार देने के लिए कैंटीन के पिछले हिस्से की दीवार को ठेकेदार द्वारा तुड़वाया जा रहा था। इस दौरान पिलर टूट गया। इस पिलर पर महिला प्रतीक्षालय का लोड था। इससे प्रतीक्षालय की छत गिर गई। हादसे के बाद यात्रियों को हटाकर प्रतीक्षालय बंद कर दिया गया।

करते रहे लीपापोती

मामले में अफसर लीपापोती करते

नजर आए। रेलवे प्रशासन मामले को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और आईआरसीटीसी के पाले में डालता रहा। देर शाम तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर ही नहीं पहुंचा।

बच गए श्रमिक, जा सकती थी जान

कार्यस्थल पर मजदूर काम कर रहे थे। छत गिरने के महज कुछ देर पहले ही मजदूर वहां से दूसरी जगह पर गए थे। ऐसे में अगर मजदूर मौके पर मौजूद होते तो उनकी जान जा सकती थी। फिलहाल रेलवे प्रशासन मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है।

लखनऊ जंक्शन पर महिला प्रतीक्षालय से जुड़ी छत गिर गई। इसके ऊपर प्रथम तल पर महिला व पुरुष एसी वेटिंग रूम था। छत गिरने से तीनों प्रतीक्षालयों को खाली करवाया गया। साथ ही उन्हें बंद भी कर दिया गया। ऐसे में अब यात्रियों के लिए स्टेशन पर प्रतीक्षालय की सुविधा फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है।

रेलवे सिस्टम पर सवालिया निशान, करोड़ों के खर्च पर उठे सवाल

(जीएनएस)। लखनऊ जंक्शन स्टेशन परिसर में स्थित एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई इस घटना में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस मलबे ने रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही की परतों को जरूर बेनकाब कर दिया है।

10 साल से अनसेफ फिर मरम्मत पर क्यों बहे करोड़ों?

जानकारों के मुताबिक, जिस बिल्डिंग की छत गिरी है, वह पिछले एक दशक से जर्जर थी और उसे बहुत पहले ही 'अनसेफ' घोषित कर गिराने (डिस्मेंटल) का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर बिल्डिंग गिराने लायक थी, तो सालों तक इसकी 'मरम्मत' के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये क्यों पानी की तरह बहाए गए? आरोप है कि यह महज मरम्मत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित 'बजट खपाऊ' खेल था।

जांच के घेरे में गतिशक्ति के चीफ इंजीनियर

विभागीय सूत्रों की मानें तो इस पूरे खेल के पीछे पूर्व सीनियर डीईएन (समन्वय) की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही हैं, जो करीब पांच साल तक लखनऊ मंडल में तैनात रहे। वर्तमान में वे प्रमोट होकर गोरखपुर में चीफ इंजीनियर/कंस्ट्रक्शन-5 (गतिशक्ति) के पद पर आसीन हैं। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान बिल्डिंग को डिस्मेंटल करने के बजाय मरम्मत का दिखावा कर भारी बजट ठिकाने लगाया गया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है।

सुरक्षा में चूक या लीपापोती की कोशिश?

घटना के बाद रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) ने इसे 'प्लैन्ड कंस्ट्रक्शन' का हिस्सा बताया है। लेकिन गिरती छत की तस्वीरें, नंगे तार और मलबे का ढेर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।

अगर यह काम सुनियोजित था, तो मजदूरों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या रेलवे अब 'जॉइंट नोट' के जरिए इस गंभीर लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है?

रोटेशन का अभाव और सिस्टम की विफलता

इस घटना ने रेलवे की पुरानी 'रोटेशन' नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही अधिकारी का लंबे समय तक एक ही जगह जमे रहना सिस्टम में भ्रष्टाचार के कैंसर की तरह फैल रहा है। लखनऊ जंक्शन की यह गिरी हुई छत चीख-चीख कर कह रही है कि फाइलों में दर्ज 'करोड़ों की मरम्मत' केवल कागजी थी। यदि इस 'इंजीनियरिंग घोटाले' की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो भविष्य में किसी बड़े जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी?

पत्नी का घोंटा गला, ई-रिक्शा से लाश को लगाया ठिकाने, पुलिस से बोला मिल नहीं रही.. फिर ऐसे पकड़ाया पति अल्ताफ

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई. लेकिन पुलिस ने शक के आधार सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली. चिनहट इलाके में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर दी. इतना ही नहीं शव को बोरे में भरकर इंदिरा डैम के किनारे फेंक आया. इसके बाद सुबह उठकर थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। शक होने पर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

अवैध सम्बन्धों के शक में पति ने की पत्नी की हत्या।

पुलिस के मुताबिक, चिनहट थाना क्षेत्र निवासी अल्ताफ उर्फ कल्लू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था. अल्ताफ को शक था कि उसकी पत्नी यास्मीन के अवैध संबंध हैं. बुधवार रात इसी बात को लेकर

दोनों के बीच विवाद भी हुआ था. जिसके बाद उसने अपनी 24 वर्षीय पत्नी यासमीन की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर ई-रिक्शा से इंदिरा डैम के किनारे फेंक आया. शव फेंकने के बाद अल्ताफ सो गया. सुबह पुलिस को गुमराह करने के लिए वह चिनहट थाने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा.

पुलिस को किया गुमराह

उसने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी कहीं चली गई है. पुलिस दिनभर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने शक आधार पर अल्ताफ से पूछताछ की. कड़ाई से पूछने पर अल्ताफ ने हत्या की बात कबूल ली. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर इंदिरा डैम के पास से यास्मीन का शव बरामद कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.